

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18, 1995 (फाल्गुन 27, 1916)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 1995 (PHALGUNA 27, 1916)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 343	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ *
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	241	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	203
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	399	भाग III—खण्ड 2—वेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई वेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	217
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, प्रादेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	493
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	35
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के प्रमाणों को बताने वाला अनुपूरक	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	343	PART II—SECTION 3—SUB SECTION. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	241	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	203
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	399	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	217
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	493
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	35
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(सांख्यिकीय विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 फरवरी, 1995

सं० एम० 13011/1/95-प्रशा०-4—राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद् की संविधान तथा कार्य-कलापों के बारे में भारत सरकार के दिनांक 5 मार्च 1970 के संकल्प संख्या डी० एस०/एस० टी० एस०/4-69, जिसमें इस विभाग के दिनांक 26 मार्च, 1984 की अधिसूचना सं० एम० 13011/2/80-रा० प्र० सर्वे०-II द्वारा यथा संशोधन किया गया था, के अनुसरण में, निम्नलिखित सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद् के सदस्यों के रूप में दिनांक 1 जनवरी, 1995 से 2 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है :—

गैर-सरकारी सदस्य

1. श्री एस० एम० विश्वन्स,
अवैतनिक निदेशक,
इंडियन स्कूल आफ पोलिटिकल इकॉनोमी,
“अर्थ बोध”,
968/21-22, सेनापति बपत रोड,
पुणे-411053।
2. प्रो० यू० शंकर,
अर्थमितीय विभाग,
मद्रास विश्वविद्यालय,
मद्रास - 600005।
3. प्रो० वैद्यनाथ मिश्रा,
अवैतनिक फेलो,
नयकूनना चौधुरी सेंटर फॉर डेवेलपमेंट स्टडीज,
भुवनेश्वर - 751013।

4. प्रो० टी० जे० राव,
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान,
203, बी० टी० रोड,
कलकत्ता-700035।

5. प्रो० अरीजीत चौधुरी,
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान,
203, बी० टी० रोड,
कलकत्ता-700035।

सरकारी सदस्य :

1. निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी ब्यूरो,
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद।
2. निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी,
असम सरकार,
गुवाहाटी।
3. पंजाब सरकार के आर्थिक सलाहकार,
चंडीगढ़।
4. मुख्य आर्थिक सलाहकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
नई दिल्ली-110001।
5. आर्थिक सलाहकार,
उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक विकास विभाग,
नई दिल्ली - 110001।

डी० एस० सेठी
अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग).

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च, 1995

लिपिक श्रेणी परीक्षा (समूह "घ" कर्मचारियों के लिए)

1995

नियम

सं० 9/1/95-के०से०—II—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा शाखा(ख) के ग्रेड-VI के अवर श्रेणी ग्रेड, संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में नियमित रूप से नियुक्त ग्रुप "घ" कर्मचारियों के लिए आरक्षित अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन् 1995 में ली जाने वाली क्लर्क ग्रेड परीक्षा (समूह "घ" कर्मचारी), 1995 अर्हक परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

जो उम्मीदवार परीक्षा में प्रविष्ट किए जाएंगे वे निम्न-लिखित सेवाओं की रिक्तियों के पात्र होंगे :—

- (i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, यदि वे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मुख्यालय कार्यालय में कार्य कर रहे हैं।
- (ii) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा यदि वे सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में नियुक्त है,
- (iii) भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड-VI यदि वे विदेश मंत्रालय या विदेश में इसके दूतावासों में नियुक्त है, और
- (iv) संसदीय कार्य मंत्रालय में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में, यदि वे संसदीय कार्य विभाग में कार्यरत हैं।

2. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या इस परीक्षा में प्रतिभागी प्रत्येक संवर्ग प्राधिकरणों द्वारा निश्चित की जाएगी।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों में परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा। किस तारीख और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी इसका निश्चय आयोग द्वारा किया जाएगा।

4. कोई भी स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी ग्रुप "घ" कर्मचारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो परीक्षा में बैठने का पात्र होगा :—

5. सेवा अवधि : (1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में अथवा (ii) सशस्त्र सेना मुख्यालय और/अथवा सेवा संगठनों अथवा

(iii) विदेश मंत्रालय/विदेशों में इसके दूतावासों अथवा (iv) संसदीय कार्य विभाग में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में अथवा किसी उच्चतर ग्रेड में 1-8-1995 को कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा की हो।

टिप्पणी : 1 —यदि किसी अभ्यर्थी की कुल गणनीय सेवा आंशिक रूप से किसी मंत्रालय या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा वाले किसी कार्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा वाले कार्यालय या विदेश मंत्रालय और इसके विदेश स्थित दूतावासों या संसदीय कार्य विभाग में श्रेणी "घ" कर्मचारी के रूप में और आंशिक रूप से अवर श्रेणी लिपिक (तदर्थ) के पद पर हों तो भी पांच वर्ष की अनुमोदित और नियमित सेवा की सीमा लागू होगी।

टिप्पणी : 2 —जो ग्रुप "घ" कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर वे अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जो ग्रुप "घ" कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त किया गया है अथवा स्थानांतरण पर अन्य सेवा में और फिलहाल ग्रुप "घ" के पद पर उसका ग्रहणाधिकार बना हुआ है वह भी अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने का पात्र है।

II. आयु—वह 1-8-1995 को 50 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए अर्थात् 2-8-1995 से पहले उसका जन्म न हुआ हो। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है तो उपर्युक्त निर्धारित आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जा सकती।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी।

III. शैक्षणिक अर्हता : भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय को मैट्रिक की परीक्षा अथवा माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय के अंत में किसी राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या कोई अन्य प्रमाण पत्र जो राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सेवाओं में प्रवेश के लिए मैट्रिक प्रमाणपत्र के समकक्ष माना जाता है, वह परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा अवश्य पास होनी चाहिए।

टिप्पणी : 1— यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसके पाम करने से वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से पात्र हो जाएगा परन्तु जिसका परिणाम उसे सूचित न किया गया हो तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का विचार कर रहा है। वह परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी 2 : कुछ विनिर्दिष्ट मामलों में जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है। जब्त कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है जो उस सरकार की साथ में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन) न हो।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

- (i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है,
- (ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
- (iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा
- (iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र-प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा
- (v) गलत या झूठे बयान दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
- (vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपयोग का सहारा लिया है, अथवा
- (vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके जतन हैं, अथवा
- (viii) परीक्षा भवन में किसी अन्य प्रकार का दुर्व्यवहार करता, अथवा
- (ix) असंगत सामग्री लिखना जिसमें पांडुलिपि में अश्लील भाषा या अश्लील सामग्री भी शामिल है, या
- (x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्रक ले गया हो या इसे किसी अनाधिकृत व्यक्ति को दिया हो, अथवा
- (xi) परीक्षाओं के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्ति किए गए कर्मचारियों को परेशान करना अथवा शारीरिक क्षति/चोट पहुंचाना, या
- (xii) उम्मीदवारों की परीक्षा में बैठने की अनुमति संबंधी उनके प्रवेश पत्र के साथ जारी किए गए किसी अन्य आदेश का उल्लंघन करना, अथवा

(xiii) पूर्व उक्त धाराओं में उल्लिखित सभी अथवा कोई एक आचरण करने का प्रयास करना अथवा यथाशक्ति उसको अभिप्रेषित करना।

फौजदारी के मुकदमे का भागी होने के अतिरिक्त उस पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकती है :—

- (क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जितना वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा
- (ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :—
 - (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,
 - (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वंचित किया जा सकता है, और
- (ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

9. परीक्षा के बाद आयोग प्रत्येक संबंधित संवर्ग प्राधिकारी को इस परीक्षा में भाग लेने वाले उन उम्मीदवारों के नामों की अलग से सिफारिश करेगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए अर्हक मानक प्राप्त करेंगे। उन उम्मीदवारों के नाम जिन्हें कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है उनका नाम एकल सूची में उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनके मूल समूह "क" पदों में रखा जाएगा। उच्च श्रेणी में पद धारण करने वाले कर्मचारी निम्न श्रेणी के कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे। संवर्ग प्राधिकारी अपने द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार भरी जाने वाली निर्णित की गई रिक्तियों पर उनकी नियुक्ति करने के कदम उठाएंगे।

10. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारों के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हों। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की चिकित्सा की परीक्षा की जाएगी जिनके बारे में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो।

टिप्पणी : विकलांग भूतपूर्व रक्षा सेवाओं के कामियों के मामले में रक्षा सेवाओं के सैन्य विघटन चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

11. इस परिणाम के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों के साथ एक शर्त यह होगी कि यदि उम्मीदवार के सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल अथवा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान अथवा अधीनस्थ सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग/राजभाषा विभाग के अधीन हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा की गई अंग्रेजी या हिन्दी की कोई आवर्ती टंकण परीक्षा पहले ही पास न हो तो यह नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संचालित अंग्रेजी में 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से ऐसी परीक्षा पास करेगा। ऐसा न करने पर जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक उसे वार्षिक वृद्धि (वृद्धियाँ) नहीं दी जाएंगी।

दृष्टिगत विकलांग अभ्यर्थियों को अंग्रेजी में 300 शब्द और हिन्दी में 250 शब्द टंकण के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा।

यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा की अवधि में उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो उसे अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में नियुक्त करने से पूर्व मूल नियुक्ति पर अथवा अस्थायी पद पर लौटा दिया जाएगा।

टिप्पणी :—परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त जिन उम्मीदवार ने उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण परीक्षा पहले ही पास की हो या जो अपनी नियुक्ति के 6 मास के भीतर टंकण परीक्षा पास कर लेगा उसे पहली बेतन वृद्धि एक वर्ष के बजाए छः महीने के बाद ही दी जाएगी, परन्तु इसे बाद में नियमित बेतनवृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

12. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपने ग्रुप "घ" पद की नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा किसी कारणवश नौकरी छोड़ देता है अथवा उससे संबंध-विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा वह किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा किसी अन्य सेवा में स्थानांतरण पर नियुक्त हो जाता है और ग्रुप "घ" पद पर उसका पुनः ग्रहणाधिकार नहीं रहता है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस ग्रुप "घ" कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगी, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति नियुक्त किया गया है।

करतार सिंह
अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्न योजना के अनुसार होगी :—

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय प्रत्येक विषय के पूर्णक इस प्रकार होंगे :—

पत्र सं०	विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1.	सबु निबंध	100	1½ घंटा
2.	सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिन्दी	50	1 घंटा
3.	भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान	50	1 घंटा

2. परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में दर्शाया गया है।

टिप्पणी : 1—जो अभ्यर्थी प्रश्न पत्र—I और III का उत्तर अंग्रेजी में देंगे उन्हें प्रश्न पत्र—II अर्थात् भाषा परीक्षण का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) लिपि में देना होगा, तथा जो अभ्यर्थी प्रश्न पत्र—I और III का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में देंगे उन्हें प्रश्न पत्र—II का उत्तर अंग्रेजी में देना होगा।

टिप्पणी : 2—दृष्टिगत विकलांग अभ्यर्थियों को तीनों प्रश्न पत्रों में से प्रत्येक के लिए आधा घंटा अनिवार्य समय दिया जाएगा।

टिप्पणी : 3—जो अभ्यर्थी परीक्षा के प्रश्न पत्र I और III का उत्तर अंग्रेजी में देने के इच्छुक हों, वे आवेदन पत्र के संगत कालम में ऐसा करने की अपनी इच्छा को निर्दिष्ट कर। अन्यथा यह माना जाएगा कि वे प्रश्न पत्र I और III का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में तथा प्रश्न पत्र II का उत्तर अंग्रेजी में देना चाहते हैं।

टिप्पणी : 4—एक बार चुना हुआ विकल्प अंतिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध माध्या-
रणतया स्वीकार नहीं होगा।

टिप्पणी : 5—उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के विषय किसी अन्य भाषा में उत्तर देने पर कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

3. अभ्यर्थियों को उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। किसी भी परिस्थिति में उनका उत्तर लिखने के लिए किसी मुंशी (स्काइव) की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दृष्टिगत विकलांग व्यक्तियों को प्रश्न पत्र ब्रेल लिपि में दिया जाएगा।

4. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

5. केवल छिछले ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

6. अस्पष्ट लिखावट के लिए पूर्णांक के 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे।

7. परीक्षा के विषयों में आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से ठीक-ठीक की गई अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

अनुसूची

पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र—I. लघु निबंध :

दिए गए कई विषयों में से किसी दो पर निबंध लिखना होगा।

प्रश्न पत्र—II. सामान्य अंग्रेजी/सामान्य हिन्दी :

उम्मीदवारों की साधारण बंध रचना, व्यावहारिक व्याकरण तथा प्रारंभिक सारणीकरण (आंकड़ों को संकलित करने तथा सारणी के रूप में उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की कला में उम्मीदवारों की योग्यता जांचने के लिए) में परीक्षा ली जाएगी।

प्रश्न पत्र—III. भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान :

सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो, आशा की जा सकती है। इस पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 फरवरी, 1995

संकल्प

भं० 11 (1)/86--एफ० डी० ए०-1 एफ० पी० 11--
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संख्या सं० 163/23/
77-एफ० डी० (ए०), दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 के द्वारा
उर्वरकों के प्रतिधारण मूल्य पद्धति का प्रशासन तथा संचालन

करने के लिए उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ० आई० सी० पी०) का गठन किया गया है। उपरोक्त समिति में उर्वरक उद्योग से प्रतिनिधियों को नामित किया जाना--कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था और अब श्री यू० एम० अवस्थी, प्रबन्ध निदेशक, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि० (इफको) और श्री के० एम० राजू, प्रबन्ध निदेशक, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० (एन० एफ० सी० एल०) को उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के सदस्य के रूप में दो वर्षों की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से नामित करने का निर्णय लिया गया है।

2. इसे पहले के दिनांक 30 जनवरी, 1995 के सम-संख्यक संकल्प के अतिक्रमण में जारी किया जा रहा है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालयों को तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को प्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

मसीम अहमद
संयुक्त सचिव

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

(संकल्प)

सं० 6(4)/91-डी० पी० आर०/ई० जी० जी०एस० 1--
औद्योगिक गैस विकास नाभिका के पुनर्गठन से संबंधित भारत सरकार के दिनांक 21 अप्रैल, 1993 के संकल्प सं० इंड० गैस/9(2)/93 में आंशिक संशोधन करते हुए, सरकार एतद्-द्वारा क्रम सं० 14 के स्थान पर निम्नलिखित परिवर्तन करती है :--

क्र० सं०

14. श्री एस० सी० सरकार, सदस्य
वरिष्ठ प्रौद्योगिकी विद्व,
क्रायो टेकनालाजी विभाग,
एडवांस सेन्टर आफ क्रायोजेनिक रिसर्च,
जादवपुर विश्वविद्यालय कैम्पस,
पो० बा० 17005, पोस्ट ऑफिस जादवपुर
विश्वविद्यालय,
कलकत्ता-700032

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

प्रौमिला भारद्वाज
निदेशक

दिनांक 14 फरवरी 1995

संकल्प

सं० 5(5)/92-डी० पी० आर०-ई० जी० जी० एस०-1—औद्योगिक विस्फोटक के लिए विकास नामिका के पुनर्गठन से संबंधित भारत सरकार के दिनांक 22 दिसम्बर, 1994 के संकल्प सं०-5(5)/92-डी० पी० आर०-ई० जी० जी० एस०

में वार्षिक संशोधन करते हुए सरकार एतद्वारा क्रम सं०-3 व 16 के स्थान पर निम्नलिखित परिवर्तन करती है :—
क्रम सं०

3. डा० ए० एस० घोसाल, सचिव
संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक,
नागपुर—440001

16. श्री पी० सी० सियांक, सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
तामिलनाडु इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स लि०,
मद्रास-18

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

प्रौमिला भारद्वाज
निदेशक

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 1995

संकल्प

सं० 18-14/94-फाल प्रशासन-5—भारत सरकार ने दिनांक 8 नवम्बर, 1991 के संकल्प संख्या 24-2/89-फसल प्रशासन-2 के द्वारा गठित भारतीय कपास विकास परिषद का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित परिषद में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. अध्यक्ष

भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाने वाला एक गैर-सरकारी व्यक्ति।

2. उपाध्यक्ष

कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

3. सदस्य

संसद के तीन सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से)
जो संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जाएंगे।

क. संसद सदस्य

ख. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभाग का एक-एक प्रतिनिधि, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जाएंगे :—

1. आंध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. हरियाणा
4. कर्नाटक
5. मध्य प्रदेश
6. महाराष्ट्र
7. पंजाब
8. राजस्थान
9. तमिल नाडु
10. उत्तर प्रदेश
11. उड़ीसा

ग. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

- क. योजना आयोग नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।
 ख. संयुक्त सचिव (कपड़ा) कपड़ा मंत्रालय ।
 ग. निदेशक, सी० आई० आर० सी० ओ० टी०, बम्बई ।
 घ. निदेशक, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ।
 ङ. कृषि और सहकारिता विभाग में कपास से संबंधित संयुक्त आयुक्त ।
 च. नागरिक आपूर्ति विभाग का एक प्रतिनिधि ।

घ. उत्पादकों के प्रतिनिधि

मुख्य कपास उत्पादक राज्यों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित रूप से नामजद किए जाने वाले ग्यारह उत्पादक प्रतिनिधि :—

(प्रतिनिधियों की सं०)

1. आन्ध्र प्रदेश	एक
2. गुजरात	एक
3. हरियाणा	एक
4. कर्नाटक	एक
5. मध्य प्रदेश	एक
6. महाराष्ट्र	एक
7. पंजाब	एक
8. राजस्थान	एक
9. तमिलनाडु	एक
10. उत्तर प्रदेश	एक
11. उड़ीसा	एक

ङ. व्यापार के प्रतिनिधि

तीन प्रतिनिधि भारतीय कपास निगम लि० महाराष्ट्र राज्य निगम कपास उत्पादक विपणन संघ बम्बई और पंजाब राज्य निगम विपणन संघ का एक-एक प्रतिनिधि ।

च. उद्योग के प्रतिनिधि

तीन प्रतिनिधि, भारतीय कपास मिल संघ दक्षिण भारत मिल संघ और उत्तर भारत कपड़ा मिल संघ का एक-एक प्रतिनिधि ।

छ. ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाएंगे ।

4. सदस्य सचिव

निदेशक, कपास विकास निदेशालय, 14 रामजी भाई कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई ।

5. प्रेषक

(जो परिषद के सदस्य नहीं होंगे, बल्कि परिषद के विचार-विमर्श में सहायता करने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे) ।

1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका प्रतिनिधि ।
2. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि ।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग) ।
4. अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली अथवा उनका प्रतिनिधि ।
5. वनस्पति रक्षण सलाहकार, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि ।
6. राष्ट्रीय बीज निगम का एक प्रतिनिधि ।
7. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली ।

2. परिषद एक सलाहकार निकाय होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. कपास के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और कपास के उत्पादन को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना ।
2. कपास के उत्पादन तथा विपणन एवं कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने से संबंधित समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों के संबंध में सरकार को सलाह देना ।
3. वेशी तथा नियमित मंडियों में कपास की मांग पर विचार करना तथा उचित विकास कार्यक्रमों के जरिए उपर्युक्त मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के संबंध में सरकार को सलाह देना ।
4. कपास के उत्पादन के संबंध में छोटे तथा सीमांत किसानों को विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उन्हें पूरा करने के लिए उचित उपाय करने हेतु सुझाव देना ।
5. काम में संबंधित अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के बीच समन्वय करना और कपास को गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के बारे में सलाह देना, और
6. आवश्यक समझे जाने वाले अन्य संबंधित मामलों पर समय-समय पर सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित करने तथा विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों जैसे सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

4. परिषद की बैठक समय-समय पर कपास उत्पादक क्षेत्रों तथा व्यापार एवं उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होगी और भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

5. परिषद तब तक काम करती रहेगी जब तक सरकार के संकल्प द्वारा इसे समाप्त न किया जाता । परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद में उनके नामित होने की तिथि से तीन वर्ष होगा, बशर्ते भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटाया या बढ़ाया न जाए।

6. संसद के सदस्यों में से नामित होने वाले परिषद के सदस्य सांसद न रहने पर परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा-सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

मालती एस० सिन्हा
संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1995

मार्चजनिक सूचना

सं० 303/43/94-एफ(एफ)—सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दिनांक 25 जनवरी, 1995 की सार्वजनिक सूचना संख्या 303/43/94-एफ(एफ) को ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय फिल्म समारोह विनियमों को अधिसूचित किया गया था ।

2. उल्लिखित विनियमों को एतद्वारा नीचे दिए अनुसार संशोधित किया जाता है :

(क) राष्ट्रीय फिल्म समारोह विनियमों में धारा-13 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :—

फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिन्ट सहित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, उस वर्ष के मार्च मास का अंतिम कार्य दिवस होगा जिसमें पुरस्कार घोषित किए जाने हैं ।

(ख) सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार संबंधी विनियमों की धारा-8 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :—

दोनों पुरस्कारों हेतु प्रविशिष्टता प्राप्त करने की अंतिम तिथि, उस वर्ष के मार्च मास का अंतिम कार्य दिवस होगा जिसमें पुरस्कार घोषित किए जाने हैं ।

पी० गोपालन
ड्रेस्क अधिकारी

MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME
IMPLEMENTATION

(DEPARTMENT OF STATISTICS)

New Delhi-110001, the 20th February 1995

No. M. 13011/1/95-Adm. IV.—In pursuance of the Government of India Resolution No. DS/STS/4-69 dated the 5th March 1970, as amended by this Department's Notification No. M. 13011/2/80-NSS. II dated the 26th March, 1984 regarding functions and composition of the Governing Council of the National Sample Survey Organisation, the following officials and non-officials have been appointed as the members of the Governing Council of National Sample Survey Organisation for a period of two years with effect from the 1st January, 1995 :—

NON-OFFICIALS :

1. Shri S. M. Vidwans,
Honorary Director,
Indian School of Political Economy,
'ARTH BODH'
968/21-22 Senapati Bapat Road,
Pune-411053.
2. Prof. U. Shankar,
Department of Econometrics,
Madras University,
Madras-600005.
3. Prof. Baidyanath Mishra,
Honorary Fellow,
Nabakrushna Choudhury Centre for
Development Studies,
Bhubaneswar-751013.
4. Prof. T. J. Rao,
Indian Statistical Institute,
203, B.T. Road,
Calcutta-700035.
5. Prof. Arijit Chaudhuri,
Indian Statistical Institute,
203, B.T. Road,
Calcutta-700035.

OFFICIALS :

1. Director,
Bureau of Economics and Statistics,
Government of Andhra Pradesh,
Hyderabad.
2. Director, of Economics & Statistics,
Government of Assam,
Guwahati.
3. Economic Adviser to Government of Punjab,
Chandigarh.
4. Chief Economic Adviser,
Department of Economic Affairs,
New Delhi-110001.
5. Economic Adviser,
Ministry of Industry,
(Deptt. of Industrial Development),
New Delhi-110011.

D. S. SETHI,
Under Secy.MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-1, the 18th March 1995

CLERKS' GRADE EXAMINATION (FOR GROUP 'D'
STAFF) 1995

RULES

No. 9/1/95-CS-II.—The Rules for Clerk's Grade Examination (for Group D Staff), 1995 to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel & Training in 1995, for the purpose of filling temporary

vacancies reserved for regularly appointed Group D staff in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, the Armed Forces Headquarters Clerical Service, Grade VI of the Indian Foreign Service Branch (B) and posts of Lower Division Clerk in the Ministry of Parliamentary Affairs, are published for general information.

The candidates who are admitted to the examination will be eligible for vacancies.

- (i) in the Central Secretariat Clerical Service, if they are working in the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service;
- (ii) in the Armed Forces Headquarters Clerical Service if they are employed in the Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organisation;
- (iii) in Grade VI of the IFS(B), if they are employed in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad; and
- (iv) in posts of Lower Division Clerk in the Ministry of Parliamentary Affairs if they are employed in the Ministry of Parliamentary Affairs.

2. The number of vacancies to be filled up on the results of the examination will be decided by each cadre authority participating in the examination.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix to these rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary Group 'D' employee who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination :—

(i) *Length of Service* : He should have rendered on 1st August, 1995, not less than 5 years of approved and continuous service as a Group 'D' employee or in the higher Grade in Ministries/Offices participating in—

- (i) the Central Secretariat Clerical Services; or
- (ii) Armed Forces Headquarters and/or Inter-Services Organisation; or
- (iii) in the Ministry of External Affairs and its Missions abroad; or
- (iv) the Department of Parliamentary Affairs.

NOTE (1) : The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of the candidate is partly as a Group 'D' employee and partly in posts of LDC (Ad-hoc) in any Ministry or office participating in the Central Secretariat Clerical Service or in the office participating in the Armed Forces Headquarters Clericals Service or in the Ministry of External Affairs and its Missions abroad or in the Ministry of Parliamentary Affairs.

NOTE (2) : Group 'D' Employees who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. A Group 'D' employee who has been appointed to an ex-cadre posts or to another service on transfer and continuous to have a lien on a Group 'D' post for the time being will also be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

II. AGE : He should not be more than 50 years of age as on 1st August, 1995 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1945.

The age limit prescribed above will be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribe.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

III. Educational Qualifications : Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Government of India as equivalent to matriculation certificate for entry into service.

NOTE (1) : A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination, will not be eligible for admission to the examination.

NOTE (2) : In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possess qualifications, the standard of which in the opinion of Government justifies his admission to the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the Examination shall be final,

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

- (i) obtaining support for his candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means in the examination hall, or
- (viii) misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (ix) writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter in the matter in the answer book/sheet, or
- (x) taking away Question Paper or Booklet/Answer Book or Answer Sheet with him/her from the examination hall or passing it on to the unauthorised person/persons during the conduct of the examination, or
- (xi) harassing or doing bodily harm to the Staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or
- (xii) violating any of the instructions issued to candidates alongwith their admission certificates permitting them to take the examination, or
- (xiii) attempting to commit, or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

May, in addition to rendering himself liable to Criminal prosecution, be liable :—

- (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period ;

- (i) by the Commission from any examination or selection held by them, or
- (ii) by the Central Government from any employment under them, or

(c) Disciplinary action under appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

9. After the examination, the Commission will recommend separately to each cadre authority concerned participating in the examination the names of candidates, who have attained the qualifying standard, which will be determined at the discretion of the Commission. The names of the candidates who are considered by the Staff Selection Commission to be suitable for appointment on the results of the examination shall be arranged in a single list on the basis of their seniority in the parent Group 'D' post. The employees holding posts in higher grade will rank senior to these in the lower grade. The cadre Authorities shall take steps to appoint them against vacancies decided to be filled in accordance with the rules/regulations framed by them in this regard.

10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed, only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE :—In case of the disabled ex-defence Service Personnel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of an appointment.

11. All appointments on the results of this examination shall be subject to the condition that unless a candidate has already passed one of the periodical typewriting tests in English or Hindi held by the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training and Management or Subordinate Service Commission, or Staff Selection Commission/Deptt. of Official Language under Hindi Teaching Scheme, he shall pass such a test at minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute to be held by the authority designated by the Government for the purpose within a period of one year from the date of appointment, failing which, no annual increment(s) shall be allowed to him until he has passed the said test.

The VH candidates will be given 20 minutes time to type the 300 words in English and 250 words in Hindi.

If any candidate does not pass the said typewriting test within the period of probation, he is liable to be reverted to his substantive appointment or temporary post held by him before his appointment to Lower Division Grade.

NOTE : A candidate appointed on the results of the examination who has already passed the typewriting test as prescribed above or who passes it within a period of 6 months from the date of his appointment will be granted the first increment after 6 months instead of one year service. This will, however, be absorbed in the subsequent regular increment.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment as a Group 'D' employee or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by this Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien on a Group 'D' post will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Group 'D' employee who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

KARTAR SINGH
Under Secy.

APPENDIX

The examination will be conducted according to the following scheme :—

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper No.	Subject	Maximum Marks	Time allowed
I	Short Essay	100	1-1/2 hours
II	General English OR General Hindi	50	1 hour
III	General knowledge (including Geography of India)	50	1 hour

2. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule to the Appendix.

NOTE 1 : Candidates who answer the question papers I & III English will be required to answer paper II i.e. Language test in Hindi (in Devanagari script) and the candidates who answer the question paper I & III in Hindi (in Devanagari script) will be required to answer paper II in English.

NOTE 2 : The VH candidates will be given half an hour extra time for each of the three papers.

NOTE 3 : Candidates desirous of exercising the option to answer paper I & III of the examination in English should indicate their intention to do so in the relevant column of their applications. Otherwise it would be presumed that they would answer paper I & III in Hindi (in Devanagari Script) and paper II in English.

NOTE 4 : The option once exercised will be final and no request for change of option will ordinarily be entertained.

NOTE 5 : No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidates.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them. However, VH candidates will be given the papers, in Braille.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

5. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

6. Deduction upto 5% of the maximum marks will be made for illegible handwriting.

7. Credit will be given for orderly, effective and exact expressions combined with due economy of words in all subjects of examination.

SCHEDULE SYLLABUS

PAPER I :

Short Essay :—

Essays to be written on any two of the several specified Subjects.

PAPER II :

General English/General Hindi :—

Candidates will be tested in simple composition applied Grammar, and Elementary Tabulation (to test candidates' ability in the art of compiling arranging and presenting data in a tabular form).

PAPER III :

General Knowledge (including Geography of India)

Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of a scientific subject. The paper will include questions on Geography of India also.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

DEPARTMENT OF FERTILIZERS

New Delhi-110 001, the 17th February 1995

RESOLUTION

No. 11/1/86-FDA-I/FP-II.—The Fertilizer Industry Co-ordination Committee (FICC) has been set up vide the Ministry of Chemicals & Fertilizers Resolution No. 166/23/77-FD(A) dated 1st December, 1977 to administer and operate the system of retention prices for fertilizers. The nomination of representatives from the fertilizer industry on the above Committee was under consideration of the Government for sometime and it has now been decided to nominate Shri U.S. Awasthi, Managing Director, Indian Farmers Fertilizer Co-operative Limited (IFFCO) and Shri K. S. Raju, Managing Director, Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Limited (NFCL) as Member of the Fertilizer Industry Co-ordination Committee with immediate effect for a period of two years.

2. This issues in supersession of the earlier Resolution of even number dated 30th January, 1995.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NASEEM AHMAD,
Joint Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 9th February 1995

RESOLUTION

No. 6(4)/91-DPR/EGGS.—In partial modification of Government of India Resolution No. Indl. Gas/9(2)/93, dated 21-4-1993 reconstituting the Development Panel for Industrial Gases, the following substitution is hereby made against

Sl. No. 14 Mr. S. C. Sarkar,
Senior Technologist,
Deptt. of Cryotechnology,
Advanced Centre of Cryogenic Research,
Jadavpur University Campus,
P.B. 17005, P.O. Jadavpur University,
Calcutta-700 032.

—Member

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PROMILA BHARDWAJ,
Director

The 14th February 1995

RESOLUTION

No. 5(5)/92-DPR/EGGS.—In partial modifications of Government of India Resolution No. 5(5)/92-DPR/EGGS, dated 22-12-94 reconstituting the Development Panel for

Explosive Industry the following substitutions are hereby made against Sl. Nos. 3 & 16 :—

Sl. No.

Members

3. Dr. A. S. Ghoshal,
Jt. Chief Controller of Explosives,
Deptt. of Explosives,
Nagpur-440 001.

16. Mr. P. C. Cyriac, I.A.S.,
Chairman & Managing Director,
Tamil Nadu Industrial Explosives Ltd.,
304/305 (II Floor), Anna Salai,
Teynampet, Madras-18.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PROMILA BHARDWAJ,
Director

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPTT. OF AGRICULTURE & COOPN.)

New Delhi, the 1st February 1995

RESOLUTION

No. 18-14/94-CA.V.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Cotton Development Council, constituted vide Resolution No. 24-2/89-CA.II dated the 8th Nov., 1991. The reconstituted Council will be composed as follows :—

- I. CHAIRMAN A Non-Official to be nominated by the Government of India.
- II. VICE-CHAIRMAN Agriculture Commissioner,
M/o Agriculture, Deptt. of Agriculture & Coopn.,
New Delhi.
- III. MEMBERS :
 - A. MEMBERS OF PARLIAMENT Three Members of Parliament (Two from Lok Sabha and One from Rajya Sabha) to be nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs.
 - B. REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENTS One representative from each of the following State Govts. in their Deptt. of Agriculture to be nominated by the respective State Govts. :—
 1. Andhra Pradesh
 2. Gujarat
 3. Haryana
 4. Karnataka
 5. Madhya Pradesh
 6. Maharashtra
 7. Punjab
 8. Rajasthan
 9. Tamil Nadu
 10. Uttar Pradesh
 11. Orissa
 - C. REPRESENTATIVES OF CENTRAL GOVERNMENT
 - (a) One representative of the Planning Commission, New Delhi.
 - (b) Joint Secretary (Textiles)
 - (c) Director, Central Instt. of Research on Cotton Technology, Bombay.
 - (d) Director, Central Instt. for Cotton Research, ICAR, Nagpur.
 - (e) Joint Commissioner, dealing with Cotton in the Department of Agriculture & Cooperation.
 - (f) A representative of the Ministry of Civil Supplies.

- D. REPRESENTATIVES OF GROWERS Eleven Growers representatives to be nominated by the respective State Governments from the major cotton growing States as follows :—
- | | |
|-------------------|-----|
| 1. Andhra Pradesh | One |
| 2. Gujarat | One |
| 3. Haryana | One |
| 4. Karnataka | One |
| 5. Madhya Pradesh | One |
| 6. Maharashtra | One |
| 7. Punjab | One |
| 8. Rajasthan | One |
| 9. Tamil Nadu | One |
| 10. Uttar Pradesh | One |
| 11. Orrisa | One |
- E. REPRESENTATIVES OF TRADE Three representatives: one each from Cotton Corporation of India Ltd., Maharashtra State Coop. Cotton Growers Marketing Federation, Bombay and Punjab State Coöperative Marketing Federation.
- F. REPRESENTATIVES OF INDUSTRY Three representatives, one each from Indian Cotton Mills Federation, Southern India Mills Federation, Northern India Textile Mills Association.
- G. SUCH ADDITIONAL PERSONS AS MAY FROM TIME TO TIME BE NOMINATED BY THE GOVERNMENT OF INDIA.
- IV. MEMBER SECRETARY The Director,
Directorate of Cotton Development,
14, Ramjibhai Kamani Marg,
Ballard Estate, BOMBAY.
- V. OBSERVERS: (who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations.)
1. Chairman, State Trading Corporation or his representative.
 2. Agricultural Marketing Adviser, Department of Rural Development or his representative.
 3. Financial Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation.
 4. Economic & Statistical Adviser, Ministry of Agriculture, Deptt. of Agri. and Cooperation or his nominee.
 5. Plant Protection Adviser to the Govt. of India, Deptt. of Agriculture & Cooperation or his nominee.
 6. A representative of the National Seeds Corporation.
 7. Managing Director, National Cooperative Development Corporation, New Delhi.
2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—
- (i) To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of cotton, review progress thereof from time to time, and recommend measures for increasing the production of cotton;
 - (ii) To consider problems relating to the production and marketing of cotton and remunerative prices to cotton growers and advise Govt. in these matters.
 - (iii) To consider demands for different varieties of cotton in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programmes;
 - (iv) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of cotton production and suggest suitable measures for meeting the same;
 - (v) To facilitate coordination between Research and Development Programmes relating to cotton and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of cotton; and
 - (vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.
3. The Council will have the powers to set up Standing Committees, Technical Committees and Ad-hoc Committees to look into specific issues and to co-opt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.
 4. The Council will meet periodically in areas in which cotton is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.
 5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The term of the Chair-

man and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from among the Members of the Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MALTI S. SINHA,
Joint Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 6th February 1995

PUBLIC NOTICE

No. 303/43/94-F(F).—Attention is invited to the Ministry of Information and Broadcasting Public Notice No. 303/

43/94-F(F) dated 25-1-1995 notifying the National Film Festival Regulations.

2. The aforesaid Regulations are hereby amended/modifed to the extent indicated below :—

(A) In the National Film Festival Regulation, clause 13 will be read as under :—

Last date for receipt of the application along with the print in the Directorate of Film Festivals shall be the last working day in the month of March of the year in which the awards are to be announced.

(B) In the National Award for the best writing on cinema Regulations, clause 8 will be read as under :—

The last date for receipt of entries for both the awards is the last working day in the month of March of the year in which awards are to be announced.

P. GOPALAN,
Desk Officer